www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 95 | जौनपुर मंगलवार, 18 नवम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बहन रोहिणी के अपमान पर भडके तेज प्रताप

पटना, (एजेंसी)। राजद सुप्रीमो सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य से जुड़े विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन का अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव ने राजद प्रमुख लालू यादव से आग्रह करते हुए कहा कि आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में खुद गाड़ देगी। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने बताया है कि उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी के आरोप पर भाई तेज प्रताप ने सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दिया है। जनता दल जनता (जेजेडी) प्रमुख तेज प्रताप ने अपने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा,कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ, वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदोंपरिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने लिखा,जबसे मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है।

लाल किला आतंकी हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के लाल किला बम धमाके की जांच कर रही एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। एनआईए ने राष्ट्रीय राजधानी से आमिर राशिद अली नाम के शख्स को दबोचा है। बताया जाता है कि धमाके को अंजाम देने वाली द्ब20 कार इसी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमीर मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है। आमिर पर आरोप है कि उसने उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी। दिल्ली में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ह्वद्ब्र की जांच में पता चला है कि जम्मू–कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाले आमीर राशिद अली धमाके में इस्तेमाल की गई कार को खरीदने के लिए कुछ महीने पहले ही दिल्ली आए थे। यहां से कार खरीदने के बाद ही उस कार में बम को सेट किया गया। बता दें कि ह्वद्ब्र आमीर की गिरफ्तारी के अलावा इस धमाके से जुड़े अन्य संदिग्धों की भी तलाश में है। यही वजह है कि ह्वद्ब्र की जांच जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों तक पहुंच चुकी है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश,दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जांच जारी है।

नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे शपथ

बिहार , (एजेंसी)। बिहार में सरकार गठन के फॉर्मूले पर भाजपा और जदयू में सहमति बन गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार देर रात जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में छह विधायक पर एक मंत्री के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ। लोजपा (आर) के साथ छह विधायक से कम संख्या वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों चिराग पासवान, जीतनराम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा से भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार को आला नेताओं की बैठक में नई सरकार की रूपरेखा को अंतिम

रूप दिया गया। लोजपा (आर) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को लेकर बातचीत चल रही है। नीतीश ने सोमवार सुबह मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक बुलाई है। इसके बाद वह राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। मंगल या बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा और बृहस्पतिवार को नई सरकार का गठन हो सकता है। शपथ समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। 17 से 20 तारीख तक मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। 89 सीटों वाली भाजपा के हिस्से में 15, 85 सीटों वाले जदयू के 14, 19 सीटों वाली लोजपा (आर) के तीन और हम व आरएलएम के हिस्से में एक–एक मंत्री पद आएगा। भाजपा पहले की तरह दो डिप्टी सीएम बनाएगी।घ्जीत के सूत्रधार रही महिला बिरादरी से डिप्टी सीएम हो सकती है। अब सबसे पहले पांच पांडव, यानी भाजपा, जदयू, लोजपा–आर, हम व आरएलएम अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। फिर एनडीए की बैठक में सीएम चुना जाएगा। सरकार गठन के बाद विभागों के बंटवारे पर मंथन होगा। सूत्रों का कहना है, नीतीश पहले की तरह गृह विभाग और प्रशासन अपने पास ही रखेंगे। वित्त विभाग पहले की तरह भाजपा के पास होगा। अन्य विभागों पर राजग के सहयोगी दलों के नेतृत्व के बीच एक दौर की और बैठक होगी। भाजपा नेतृत्व बिहार में गठबंधन की स्थिरता को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता।

बिहार में सरकार गठन की अंतिम तैयारी, दिल्ली से पर्यवेक्षक को चुनेंगे भाजपा नेता

बिहार, (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत के बाद, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 18 नवंबर को अपने विधायक दल का नेता चुनेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार बनाने का काम 21 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कल सुबह 10 बजे भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में भाजपा अपना नेता चुनेगी। केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक भी आएंगे, और फिर एनडीए की बैठक होगी, और फिर सरकार गठन का काम पूरा हो जाएगा। 21 तारीख तक सरकार गठन का काम पूरा हो जाएगा। इससे पहले सोमवार को, भाजपा सांसद जनार्दन सिंह

सिग्रीवाल ने भी पुष्टि की कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पत्रकारों से बात करते हुए, सिग्रीवाल ने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सरकार जल्द ही आकार ले लेगी। लोगों ने हमें भारी जनादेश दिया है और हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। लोगों ने विकास और विश्वास के आधार पर वोट दिया है। लोगों ने के मुद्दे को खारिज कर दिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया

मुंबई, (एजेंसी) महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी कर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने शिवसेना के संस्थापक और हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रखर नेता बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि से पहले यह अहम फैसला लिया। राज्य सरकार ने बालासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की

भी नई नियुक्ति की है। आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। भाजपा विधायक पराग अलवानी और शिवसेना नेता शिशिर शिंदे को भी स्मारक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। बालासाहेब ठाकरे की स्मृति को संजोए रखने के लिए मुंबई में एक भव्य स्मारक बनाने के लिए शिवाजी पार्क, दादर स्थित श्मेयर बंगलाश परिसर का चयन किया गया। इस स्मारक के लिए एक सरकारी सार्वजनिक न्यास की स्थापना की गई। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्मारक निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट ने दो कार्यकाल पूरे किए। दूसरी बार नियुक्त सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल इसी साल 11 मार्च को पूरा हुआ। पूर्व अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जरूरी हो गई थी। आदेश में आगे कहा गया कि सरकार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, ट्रस्ट में हुए बदलाव को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने के लिए सुभाष राजाराम देसाई को ट्रस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है ।

सबरीमाला सोना चोरी मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। केरल भाजपा ने सोमवार को सबरीमाला के सोने से जुड़े विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए बड़ा कदम उठाया। पार्टी ने अयप्पा भक्तों से एक करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का अभियान शुरू किया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हस्तक्षेप की मांग की जा सके। यह अभियान मलयालम महीने वृश्चिकम के पहले दिन शुरू हुआ, यानी वह दिन जब सबरीमाला में वार्षिक तीर्थयात्रा की शुरुआत होती है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध पाझवंगड़ी गणपति मंदिर के सामने भाजपा के राज्य महासचिव एस. सुरेश ने किया। इस दौरान भाजपा के राज्य महासचिव एस. सुरेश ने कहा कि भक्तों के हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को

सौंपे जाएंगे। उन्होंने पड़ोसी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अयप्पा भक्तों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की। उनके अनुसार, श्सबरीमाला की रक्षा के लिए यह एकजुटता जरूरी है।श भाजपा नेता ने कहा कि सबरीमाला में जो हुआ, वह सिर्फ सोने की चोरी नहीं थी, बल्कि श्रद्धास्थल को चोट पहुंचाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। भाजपा नेता ने केरल की पिछली एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों पर आरोप लगाया कि वे श्सबरीमाला को कमजोर करने की कोशिशें करती रही हैं, और यह सब एजेंटों व बिचौलियों के जरिए गुप्त रूप से किया गया।श उन्होंने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय मंच पर लाया जाना जरूरी है, और हस्ताक्षर अभियान उसी दिशा में पहला कदम है। भाजपा नेताओं के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में सोमवार को हस्ताक्षर संग्रह भी शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ता दक्षिण भारत के कई राज्यों में घर–घर जाकर और सार्वजनिक स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। कुछ दिन पहले, भाजपा के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस अभियान की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सबरीमाला में सोने की परत चढ़ाने से जुड़े कामों में अनियमितताएं हुई हैं, और यात्रियों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। चंद्रशेखर ने यह भी मांग की थी कि त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की पिछले 30 वर्षों की गतिविधियों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से विशेष ऑडिट कराया जाए।

समाधान की तरफ जाना होगा,समस्या की तरफ जाएंगे तो समस्या ही मिलेगी : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। साथ में मंच पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हमें समाधान की तरफ जाना होगा। समस्या की तरफ जाएंगे तो समस्या ही मिलेगी। आज यूपी केंद्र की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तीसरे नंबर पर है। दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी के साये में

जी रही थी। तब भारत कोविड प्रबंधन के साथ भारत नेशनल एजुकेशनल पालिसी को भी बना रहा था। दीक्षांत समारोह के दौरान दो बैच के 5746 छात्रों को उपाधि दी गई। साथ ही उन्हें मेडल से नवाजा गया। सीएम योगी ने कहा, 2017 के पहले यूपी को पहचान का संकट था। युवा परेशान, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। नया निवेश की बात तो दूर जो पहले से निवेश कर चुके थे, वो पलायन कर रहे थे। भारत सरकार ने जब जीरो टॉलरेंस की बात की तो लोग कहते थे कि ये सिर्फ एक घोषणा है। अब क्या होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, बकरीद सब अच्छे से मनाया जाता है। कानून का पालन करना ही होगा। कानून व्यवस्था पर काम करने से निवेश की झड़ी लग गई। 5 वर्ष में 50 हजार करोड़ का निवेश मिलना भी मुश्किल था। उसी प्रदेश में 8 साल में 45 लाख करोड़ का निवेश आ गया।

हाथ में गुब्बारे लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि पीतमपुरा क्षेत्र के तीन मेट्रो स्टेशनों का नाम जल्द ही बदला जाएगा ताकि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और स्थानीय पहचान को उजागर किया जा सके। यह घोषणा नई दिल्ली के हैदरपुर गाँव में आयोजित श्रेष्ठ भारत संपर्क यात्रा के दौरान की गई। यह यात्रा 1962 के ऐतिहासिक रेजांग ला युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की गई थी, जहाँ 13 कुमाऊँ रेजिमेंट के 114 वीर सैनिकों ने लद्दाख में अत्यधिक ऊँचाई पर भारत की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुप्ता ने कहा कि हैदरपुर गाँव तेजी से विकसित हो रहा है और आधुनिक सुविधाओं के साथ अपनी परंपराओं को भी सहेज रहा है। उन्होंने लिखा, "हैदरपुर गाँव विकसित होती दिल्ली का प्रतीक बन रहा है, जहाँ परंपरा का सम्मान और आधुनिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।" गुप्ता ने क्षेत्र में चल रही आधारभूत संरचना परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि मैक्स अस्पताल रोड के चौड़ीकरण और अंडरपास निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और कुशल आवागमन की सुविधा मिलेगी। ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली मेट्रो वर्तमान में फेज–IV परियोजना के तहत बड़े विस्तार से गुजर रही है, जिसमें 112 किलोमीटर नई लाइनों और 44 नए स्टेशनों का निर्माण शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, इस विस्तार के बाद 2027 तक दिल्ली मेट्रो नेटवर्क लगभग 450 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सऊदी बस दुर्घटना के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया

तेलंगाना, (एजेंसी)। तंलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को अधिकारियों को सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने का निर्देश दिया, जिसमें हैदराबाद के कुछ निवासी शामिल थे। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब बस मक्का से खाड़ी देश मदीना जा रही थी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव और पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी को विदेश मंत्रालय एवं सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा है। सरकार ने दुर्घटना में शामिल लोगों के परिवारों को जानकारी प्रदान करने के लिए सचिवालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर जारी किए हैं। सऊदी अरब के मदीना में हुई सड़क दुर्घटना में कई भारतीयों के मारे जाने की आशंका है। जेद्दा स्थित भारतीय मिशन के अनुसार, बस उमराह करने गए भारतीय श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी। रूस की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, ''रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं।'' मुख्य सचिव ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के अधिकारियों को तेलंगाना के प्रभावित निवासियों की संख्या का पता लगाने को कहा है।

मैं भी इस मुश्किल दौर से गुजरा हूँ : चिराग पासवान

बिहार, (एजेंसी)। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार में बढ़ते विवाद के बीच, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वह रोहिणी द्वारा बताई गई भावनात्मक दरार को समझते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके आंतरिक विवाद जल्द ही सुलझ जाएँ। पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक मतभेद एक बात है, लेकिन वह मेरा परिवार भी हैं। जब किसी परिवार में तनाव होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि यह कितना बेचौन करने वाला हो सकता है। पासवान ने कहा कि मैं नहीं मानता कि शादी के बाद, बेटी के लिए ससुराल ही एकमात्र घर होता है। मैं इस रूढ़िवादी सोच का समर्थन नहीं करता। कल जब उन्होंने यह सब कहा, तो मैं उस

दर्द को समझ सकता था और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह सब जल्द ही सुलझ जाए। पासवान ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई परिवार ऐसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। मैं भी इससे गुजरा हूँ। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद रहे होंगे, लेकिन मैंने लालू जी के परिवार को हमेशा अपना माना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाहे तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा हों या रोहिणी, मैंने उन्हें अपना भाई–बहन माना है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए। अगर परिवार में एकता है, तो व्यक्ति बाहर भी मुश्किल परिस्थितियों से लड़ सकता है... परिवार जरूर मुश्किल हालात से गुजर रहा होगा। उनकी यह टिप्पणी रोहिणी आचार्य द्वारा ष्राजनीति छोड़नेष और अपने परिवार से ष्अलगावष की घोषणा के एक दिन बाद आई है। रोहिणी आचार्य ने अपने विस्फोटक सोशल मीडिया पोस्ट से खलबली मचा दी थी, जिसमें उन्होंने बहिष्कृत किए जाने, खुद को बेकार महसूस कराए जाने और अपने ऊपर लगे बोझ के दर्द को बयां किया था। उन्होंने लिखा, ष्कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक माँ को अपमानित किया गया, गालियाँ दी गईं, मारने के लिए जूते उठाए गए... मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, सत्य का साथ नहीं छोड़ा... बस इसी वजह से मुझे अपमान सहना पड़ा। कल एक बेटी लाचारी में अपने रोते–बिलखते माता–पिता और भाई–बहनों को छोड़कर चली गई... उसे अपना मायका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

संपादकीय

गैर–बराबरी घुन

जिस छोटे से तबके के हाथ में धन केंद्रित होता है, सरकारी नीतियों पर उसका शिकंजा कस जाता है। यानी गैर–बराबरी ऐसा घुन है, जो लोकतंत्र को कुतर डालती है। भारत में अमीर– गरीब की खाई तेजी से बढ़ी है। भारत में आर्थिक गैर–बराबरी अत्यधिक बढ़ चुकी है, यह कोई नया तथ्य नहीं है। नई बात सिर्फ यह है कि इस बार जी–20 समूह की तरफ से नियुक्त मशहूर अर्थशास्त्रियों के टास्क फोर्स ने इस ओर ध्यान खींचा है। जोसेफ स्टिग्लिट की अध्यक्षता वाले इस टास्क फोर्स ने गैर–बराबरी बढने के परिणामों का भी उल्लेख किया है। साथ ही बताया है कि इस पर किस तरह लगाम लगाया जा सकता है। फिलहाल, जी–20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की पहल पर ये टास्क फोर्स बना। उसने बताया है कि इस समस्या को नजरअंदाज करना कितना हानिकारक है। टास्क फोर्स के मुताबिक अत्यधिक आर्थिक विषमता से राजनीति पटरी से उतर जाती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन के प्रयास बाधित होते हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन रोकने की कोशिशें कमजोर पड़ती हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जिस छोटे से तबके के हाथ में धन का संकेद्रण होता है, सरकारी नीतियों पर उसका शिकंजा कसता चला जाता है। यानी यह ऐसा घुन है, जो लोकतंत्र को कुतर डालता है। टास्क फोर्स के मुताबिक भारत में अमीर और गरीब के बीच संपत्ति की खाई पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ी। साल 2000 से 2023 के बीच देश के शीर्ष एक प्रतिशत लोगों के धन में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दुनिया में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों ने 2000 के बाद से पैदा हुई नई संपत्ति का 41 प्रतिशत हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दुनिया की निचली 50 प्रतिशत आबादी की संपत्ति में सिर्फ एक प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन आंकड़ों की रोशनी में इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है कि इस दौर में भारत सहित ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में क्यों ऐसी ताकतों का उदय हुआ, जिनके राज में वहां लोकतांत्रिक आजादियां सिकुड़ी हैं। कारण है सत्ता के केंद्रों पर अत्यधिक धनवान लोगों का बना नया नियंत्र। बहरहाल, महज इस परिघटना को महज समझना पर्याप्त नहीं है। असल सवाल ऐसी राजनीति का है, जिसमें सत्ता आम जन के पास लौटाने की दृष्टि एवं संकल्प हो।

सीडीएस अनिल चौहान ने घरेलू रक्षा उद्योग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की पोल खोल दी

नीरज

भारतीय रक्षा उद्योग के सामने खड़े सबसे असहज प्रश्न कभी राजनीतिक नेताओं ने तो नहीं पूछे लेकिन यह काम सेना के सबसे ऊँचे अधिकारी यानि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान ने कर दिखाया है। जनरल अनिल चौहान की टिप्पणी कठोर है, सीधी है और उतनी ही असुविधाजनक भी, क्योंकि इससे वह वास्तविकता उजागर होती है जिसे अक्सर आत्मनिर्भरता के शोर में दबा दिया जाता है। दरअसल आपातकालीन रक्षा खरीद के पाँचवें और छठे चरण के विफल अनुभवों ने सेना को स्पष्ट रूप से निराश किया है क्योंकि तमाम घोषणाओं और "अतिस्वदेशी" दावों के बावजूद समय पर आवश्यक उपकरण नहीं मिले। जब सीडीएस कहते हैं कि "उद्योग को अपने लाभ केंद्रित प्रयासों में थोड़ा राष्ट्रवाद और देशभक्ति भी दिखानी चाहिए", तो यह सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं होती बल्कि यह सुरक्षा–स्वाभिमान के मूल प्रश्न को छूती है। उल्लेखनीय है कि EP व्यवस्था का जन्म संकटकालीन जरूरतों को देखते हुए हुआ था। उद्देश्य यह कि सेना को लंबी प्रक्रियाओं से अलग हटकर तत्काल हथियार, मिसाइलें और आवश्यक प्रणालियाँ मिल सकें। मोदी सरकार ने आपातकालीन खरीद प्रावधान

के तहत हर अनुबंध की सीमा करीब 300 करोड़ रुपए तक निर्धारित की है और इन्हें एक वर्ष के भीतर निष्पादित करने का प्रावधान है ताकि लंबी सामान्य प्रक्रियाओं की जगह तेजी से आवश्यक उपकरण जुटाए जा सकें। इस व्यवस्था के पाँचवे चरण के बाद रक्षा मंत्रालय ने को भी मंजूर किया था। लेकिन घरेलू रक्षा कंपनियाँ अनुबंध पर हस्ताक्षर तो कर देती हैं मगर एक वर्ष की समयसीमा में उपकरणों की आपूर्ति नहीं कर पातीं। यह सिर्फ देरी नहीं, सामरिक क्षमता का नुकसान है। आपातकालीन खरीद नीति की असफलता सीधे मोर्चों पर सैनिकों की तैयारी को प्रभावित करती है। अगर E ओवर– प्रॉमिस, अंडर –डिलिवर" का चलन बढ़ रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रक्षा उपकरणों के निर्माण में "70% स्वदेशी" या "80% स्थानीय सामग्री" का उपयोग जैसी घोषणाएँ गर्व तो पैदा करती हैं लेकिन जब सीडीएस स्वयं यह कहें कि वास्तविकता इससे बहुत कम है, तो यह न केवल उद्योग की विश्वसनीयता पर प्रहार है, बल्कि पूरे आत्मनिर्भरता–वृत्तांत को भी चुनौती है। विदेशी मशीनों को सिर्फ देसी पेंच से जोड़कर किसी प्रणाली को "स्वदेशी" कहना आत्मनिर्भरता की परिभाषा से खिलवाड़ है। युद्ध जैसी घड़ी में आयात पर निर्भर घटक नहीं आयें तो पूरी प्रणाली ठप हो सकती है। इसलिए भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। साथ ही सीडीएस की यह टिप्पणी कि भारतीय कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय बाजार का सामना करने लायक मूल्य–प्रतिस्पर्धा नहीं रखतीं, एक और कठोर सच्चाई उजागर करती है। सरकारी खरीद का प्रतिस्पर्धी होना बहुत जरूरी है क्योंकि महँगे हथियारों की कीमत अंततः करदाताओं से ही चुकाई जाती है। साथ ही सीडीएस का "थोड़ा राष्ट्रीयवाद" वाला कथन मूल रूप से उद्योग की नैतिक जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डालता है। राष्ट्र की सुरक्षा केवल सरकार और सेना की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि रक्षा उद्योग भी उतना ही साझेदार है। पर यह साझेदारी तभी सार्थक बनेगी जब लाभ कमाने के साथ कंपनियाँ सुरक्षा की संवेदनशीलता और समयसीमा की गंभीरता को समझें। यह भी समझना होगा कि रक्षा उद्योग केवल एक कारोबारी क्षेत्र नहीं, बल्कि रणनीतिक परिसंपत्ति है। इस क्षेत्र में अतिशयोक्ति, देरी या गैर–पारदर्शिता, किसी अन्य उद्योग की तुलना में कई गुना अधिक खतरनाक हो सकती है। यदि रक्षा उद्योग सचमुच आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ बनना चाहता है, तो उसे कुछ बुनियादी बदलावों को स्वीकार करना होगा। जैसे EP अनुबंधों पर कठोर दंडात्मक प्रावधान करने होंगे और इसके तहत समयसीमा तोड़ने पर आर्थिक जुर्माने या ब्लैकलिस्टिंग जैसे कदम उठाने होंगे। साथ ही स्वदेशीकरण का स्वतंत्र ऑडिट कराना चाहिए। इसके अलावा, माइलस्टोन आधारित अनुबंध होने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मूल्य निर्धारण होना चाहिए और R-D आधारित उद्योग मॉडल होना चाहिए क्योंकि केवल असेंबली पर आधारित उद्योग टिकाऊ नहीं होते। देखा जाये तो जनरल चौहान का बयान वास्तविक अनुभव से निकला है। उनके शब्द उद्योग को कटघरे में नहीं, बल्कि दायित्व के दायरे में लाते हैं। भारत आज ऐसे मोड़ पर है जहाँ आधुनिक युद्ध केवल सीमा पर नहीं, अंतरिक्ष से लेकर साइबर और ड्रोन–तकनीक के नए क्षेत्रों में लड़ा जा रहा है। इस नए युद्धक्षेत्र में देरी, अनिश्चितता या गलत दावे की कोई जगह नहीं है। रक्षा उद्योग यदि वही पुरानी असेंबली आधारित सोच, ऊँचे दाम और ढीली समयसीमा पर चलता रहा, तो आत्मनिर्भरता का सपना एक आकर्षक नारा तो रहेगा, पर वास्तविकता नहीं बनेगा।

अब पश्चिम बंगाल में गूंजेगा जंगलराज का मुद्दा

डॉ. आशीष

बिहार में 1990–2005 के दौरान लालू यादव–राबड़ी देवी का शासन था। उनके ही शासन को जंगल राज कहा गया। दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पहली बार बिहार में जंगलराज कहा था। पटना हाईकोर्ट ने तब कहा था– शबिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगलराज कायम हो गया है। उस दौर में अपराध के बढ़ते ग्राफ और बाहुबलियों के दबदबे के कारण हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। तब से समय–समय पर बिहार में यह गूंजता रहता है। बिहार में तो जंगल राज अब तकिया कलाम बन गया है। बात–बात में लोग जंगल राज का जिक्र करते हैं। पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी के 25 वर्ष बाद वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल के लिए पहली बार इसका प्रयोग हुआ है। संयोगवश बिहार के लिए इसका प्रयोग भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने ही किया था और अब बंगाल के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही इसका प्रयोग किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में 13 जनवरी 2023 को जस्टिस विश्वजीत बोस के सामने एक शिक्षक के तबादले का मामला सुनवाई के लिए आया। जस्टिस ने कहा कि यह जंगलराज ही होगा कि जिसकी जो मर्जी, उसी के मुताबिक काम होने लगे। ऐसा नहीं चलेगा। जिस स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, वहीं तबादला होगा। तबादले के बाद हफ्ते भर में शिक्षकों को ज्वाइनिंग देनी होगी। जंगलराज पर बात करने का ताजा संदर्भ यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचण्ड जीत के बाद नई दिल्ली में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक जीत को बंगाल में भाजपा की सफलता का मार्ग बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में जंगलराज समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया है। पीएम मोदी के इस बयान के बड़े मायने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव सभाओं में जंगल राज का मुद्दा जोर–शोर से उठाया। अब बारी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च–अप्रैल में प्रस्तावित है। कांग्रेस से निकलीं ममता बनर्जी ने साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। 13 साल बाद 2011 में ममता बनर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहाया था। इस चुनाव में टीएमसी को 184 सीटें मिली थीं। ममता बनर्जी पहली बार राज्य की सीएम बनी। 2016 में फिर से ममता ने जीत हासिल की। तब पार्टी को 211 सीटों के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई। 2021 में लगातार तीसरी बार टीएमसी ने जीत हासिल की थी। टीएमसी ने 215 सीटें जीती थीं। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी राज्य में जीत की हैट्रिक जड़ चुकी है। 2026 के चुनावों में टीएमसी का मुकाबला बीजेपी से होगा। पिछले डेढ दशक के टीएमसी के शासन में चुनावी हिंसा से लेकर, विपक्ष खासकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा और हत्या, महिला शोषण व अत्याचार के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले प्रकाश में आए हैं। ममता सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार निशाना साधती रही है। ममता सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने शिक्षक नियुक्ति में महा घोटाले को उजागर किया है। इसी मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री समेत कई अधिकारी आरोपी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो सैकड़ों नियुक्तियां रद्द भी की हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट भी ममता सरकार के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। संदेशखाली हो या फिर अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से बलात्कार का मामला प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये और बयानबाजी से आमजन अंदर ही अंदर बेहद नाराज है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में ही होती है। दरअसल, इस राज्य में दंभ के स्वरों की गिनती में हिंसा का शीर्ष स्थान है और हिंसा को हमेशा शक्ति प्रदर्शन की श्रेणी में रखा गया। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो! चाहे आम चुनाव हो या उप चुनाव ही क्यों न हो! चाहे वह प्री पोल वायलेंस हो या पोस्ट पोल वायलेंस! पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा की गठरी हमेशा बंधी रही। सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुईं। जबकि, उस साल अगस्त में सीपीएम ने एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 62 काडरों की हत्या कर दी। हिंसा का जहां तक सवाल है, खासकर 2018 पंचायत चुनाव से 2021 के विधानसभा चुनाव तक राज्य में काफी हिंसा देखने को मिलीं। खासकर विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने तो काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का राज है और विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। पश्चिम बंगाल में 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े प्रमाण के तौर पर पेश किए जाते हैं। एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई और देश में बंगाल इस मामले में पहले स्थान पर था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की दो लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देना शुरू कर दिया। 2016 के चुनाव में हालांकि बीजेपी को महज तीन सीटें मिलीं, लेकिन उसका वोट शेयर 4 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी पर पहुंच गया। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली जब वो राज्य की 42 में 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहीं। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी ने अपना किला बचाए रखा और राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 215 पर जीत दर्ज की. हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की और 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ और वह 12 सीटों पर सिमट गई। 2011 में लेफ्ट सरकार के पतन के बाद लोगों को उम्मीद जगी कि अब सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा–लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल में हिंसा कम नहीं हुई। अब तो बिना किसी चुनाव के भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पर हमला आम बात हो गई है। जबकि 1977 में कांग्रेस और 2011 में लेफ्ट फ्रंट सरकार की विदाई के पीछे कई वजहों में मुख्य वजह राजनीतिक हिंसा भी थी। ऐसे में आखिर कैसे बदलेगी यह तस्वीर! बीजेपी पिछले लंबे समय से पश्चिम बंगाल में जंगलराज का मुद्दा उठाती रही है। पीएम के बयान के बाद ये बात साफ हो गई है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जंगलराज का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। जिस तरह की गंभीर घटनाएं पिछले डेढ़ दशक में पश्चिम बंगाल में घटी हैं, उसके चलते टीएमसी के लिए पलटवार करना आसान नहीं होगा। 2026 में ममता पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल होंगी या बीजेपी सरकार बनाएंगी ये तो आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव की टोन सेट कर दी है।

आंखों में जलन है, गले में खराश है, सीने में तूफान

अजीत

हर साल नवंबर, दिसंबर में दिल्ली में हिंदी फिल्मों का यह गाना खूब चर्चा में रहता है कि 'आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यूं है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यूं है'। इस साल भी ऐसा ही है। आंखों में जलन है, गले में खराश है, सीने में तूफान सा है, अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन फर्क यह है कि इस बार सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता ज्यादा खराब नहीं हुई है। दिल्ली में नंगी आंखों से हवा प्रदूषित दिख रही है और लोग उसे महसूस कर रहे हैं। यह साफ दिख रहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 'गंभीर श्रेणी' में है या चार सौ से कम नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि एक्यूआई पहले 'बेहद खराब श्रेणी' में थी लेकिन अब सुधार हुआ है और अब वह 'खराब श्रेणी' में आ गई है। इसका मतलब है कि एक्यूआई तीन से आसपास थी, जो अब दो सौ या उससे नीचे आ गई है। वास्तविकता और आंकड़ों का यह फर्क इसलिए आया दिख रहा है क्योंकि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है। 27 साल के बाद सत्ता में लौटी भाजपा की सरकार यह साबित करने में लगी है कि उसने नौ महीने के ही अपने राज में हवा की गुणवत्ता सुधार दी है। हालांकि दिल्ली सरकार अपनी पोल खुद ही खोल रही है। एक तरफ उसकी एजेंसियां कह रही हैं कि वायु गुणवत्ता में कभी भी बहुत ज्यादा खराबी नहीं आई है। उसने 'खराब श्रेणी' का दावा किया है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण लागू किया है। लेकिन दूसरी ओर सरकार खुद ही ऐसे उपायों को लागू कर रही है, जो प्रदूषण बढने पर ग्रैप के दूसरे चरण में लागू किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले नगर निगम ने बुधवार, 29 अक्टूबर को पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया। ग्रैप का दूसरा चरण लागू करने पर यह किया जाता है। इसी तरह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने फेरे 30 फीसदी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। प्रदूषण बढने पर ही सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं में बढ़ोतरी की जाती है। ऐसे ही एक नवंबर से बीएस छह से नीचे के व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश रोकने की घोषणा कर दी गई है। सो, सरकार ऐसे उपाय कर रही है, जिससे लग रहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा है लेकिन दूसरी ओर वह इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। उलटे ऐसे आंकड़े पेश कर रही है, जिससे लग रहा है कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है। इसी तरह दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने का भी प्रयास किया। आईआईटी कानपुर के साथ मिल कर इसके दो ट्रायल हुए। हालांकि सरकार और आईआईटी दोनों को पता था कि हवा में नमी 10 फीसदी से ज्यादा नहीं है और 50 फीसदी से कम नमी होने पर क्लाउड सीडिंग काम नहीं करता है। फिर भी करीब दो करोड़ रुपए खर्च करके क्लाउड सीडिंग की गई। इसका कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि बारिश नहीं हुई। तब सरकार ने यह दावा शुरू कर दिया कि बारिश भले नहीं हुई है लेकिन इससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिली है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि हवा में मौजूद खतरनाक धूल कणों में से एक पीएम 10 में 42 फीसदी की कमी आई है। हालांकि यह ट्रायल करने वाले आईआईटी का कहना है कि पीएम 10 में छह से 10 फीसदी तक की कमी आई है। सोचें, सरकार क्या बढ़ा चढ़ा कर पीएम 10 कम होने का दावा कर देगी तो लोगों को प्रदूषण से राहत मिल जाएगी? ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सरकार हर जगह आंकड़े छिपा कर हकीकत बदलने की कोशिश कर रही है। इस बार दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर दिल्ली में पटाखों की बिक्री शुरू कराई। अदालत ने हालांकि तीन दिन तक ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत दी थी लेकिन कई दिन तक पटाखे बिके और दिवाली पर खूब पटाखे चले। फिर भी दिवाली के अगले दिन कहा गया कि वायु प्रदूषण नहीं बढ़ा है। दावा किया गया कि एक्यूआई तीन सौ आसपास रहा यानी 'बेहद खराब श्रेणी' तक ही हवा की क्वालिटी बिगड़ी। हालांकि बाद में खबरें आईं कि दिवाली की रात को जिस समय एक्यूआई सबसे ज्यादा बिगड़ी उस समय के आंकड़े नहीं जोड़े गए। यानी दिवाली के अगले दिन का एक्यूआई पीक पॉल्यूशन के आंकड़ों के बगैर निकाला गया। सोचें, आंकड़ों के साथ ऐसी धोखाधड़ी कोई जिम्मेदार सरकार कैसे कर सकती है? अभी जो भी प्रदूषण है उसके लिए दिल्ली सरकार ने सारा ठीकरा पंजाब पर फोड़ दिया है। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार भाजपा शासित राज्यों में पराली जलाए जाने को दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताती थी वैसे ही भाजपा की दिल्ली सरकार पंजाब की आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली में प्रदषण बढ़ा है। हवा के साथ साथ यमुना की सफाई के मामले में भी दिल्ली सरकार का यही रवैया है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद पहले दिन से दिल्ली सरकार और भाजपा नेताओं ने यमुना में सफाई का कथित अभियान शुरू किया। ड्रेजिंग करने वाली मशीनें लगा दी गईं।

हम अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं चक्रव्यूह बेधेंगे और बाहर भी आएंगे - राहुल

शकील

बहार में वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई 89 सीटों के साथ। क्या यहां भी वह महाराष्ट्र को दोहराएगी? सवाल सबके मन में है। मगर जवाब बहुत मुश्किल। मोदी बिल्कुल कोशिश करेंगे। अपना मुख्यमंत्री बनाने तक। मगर नीतीश को शिन्दे की तरह उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। हां, नीतीश को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वादा करके अपना मुख्यमंत्री जरूर बनवा सकते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था अभिमन्यु की तरह घेर कर मार नहीं पाओगे। उन्होंने भाजपा द्वारा चक्रव्यूह रचने की बात करते हुए कहा था कि भारत के लोग अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं तोड़ कर बाहर निकल आएंगे। देश की आम जनता के साथ राहुल ने फिर यह बात अलग–अलग जगह युवा, पिछड़ों, दलितों के लिए भी कही। यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप समझना चाहें तो यही उनकी राजनीति। लोगों पर विश्वास। और इसके साथ ही ठीक इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति है जहां जनता तो छोड़िए खुद अपनी पार्टी पर ही उन्हें विश्वास नहीं है। इसके दो उदाहरण। एक राहुल ने यह जो भाजपा द्वारा लोगों को चक्रव्यूह में फंसाए रखने की बात कही थी वह मोदी के लोकसभा में इसी गर्वोक्ति के बाद कही थी जिसमें उन्होंने खुद को अकेला ही सबसे लड़ने में समर्थ बताया था। एक अकेला सब पर भारी। और दूसरा उनकी ही पार्टी के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने कहा था कि बिना मोदी के भाजपा कुछ नहीं है। चुनाव नहीं जीत सकती। अब बिहार के बाद यह कहा जा सकता है कि मोदी चुनाव ही नहीं जीतते बल्कि इतने ज्यादा बहुमत से जीतते हैं कि किसी को विश्वास ही नहीं होता। जनता तो पूरी तरह हैरान रह जाती है।सब कह रहे हैं कुछ ज्यादा हो गया। भाजपा का 88 प्रतिशत स्ट्राइक रेट। उस राज्य में जहां वह कभी प्रमुख दल भी नहीं रही। बिहार में पहले कांग्रेस फिर लालू और फिर नीतीश की पार्टियां प्रमुख दलों में रहीं। मगर मोदी चुनाव आयोग से मिलकर यह कारनामा पिछले साल महाराष्ट्र में भी अंजाम दे चुके हैं। वहां 85 प्रतिशत का स्ट्राइक रेट। वहां भी भाजपा की गिनती कभी प्रमुख दलों में नहीं रही। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ही वहां प्रमुख दल रहे। मगर 2024 में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 132 सीटों के साथ। अपना मुख्यमंत्री बना लिया। एकनाथ शिन्दे जो चुनाव नतीजों तक मुख्यमंत्री थे उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने पर मजबूर कर दिया।बिहार में वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई 89 सीटों के साथ। क्या यहां भी वह महाराष्ट्र को दोहराएगी? सवाल सबके मन में है। मगर जवाब बहुत मुश्किल। मोदी बिल्कुल कोशिश करेंगे। अपना मुख्यमंत्री बनाने तक। मगर नीतीश को शिन्दे की तरह उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। हां, नीतीश को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वादा करके अपना मुख्यमंत्री जरूर बनवा सकते हैं। मोदी इस समय क्या कर सकते हैं कोई नहीं बता सकता। उनके पास अकूत ताकत है। सारी संवैधानिक संस्थाएं हथियार डाल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कुछ नहीं किया। 65 लाख वोट काट दिए गए। अभी केरल कांग्रेस ने 128 सीटों के आंकड़े देकर बताया कि किस तरह वोट काटने से वहां एनडीए जीता है। वोटर लिस्ट का काम कांग्रेस का करना पड़ रहा है।कांग्रेस ने कहा कि वह दो हफ्ते में वह चुनाव धांधलियों के सारे सबूतों के साथ जनता के सामने आएगी। राहुल इससे पहले भी कर्नाटक में वोट चोरी और फिर हरियाणा की वोट चोरी के सबूत दे चुके हैं। मगर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब संवैधानिक संस्थाएं खामोश हैं। एक अकेला राहुल सबसे लड़ रहा है। ऐसी अविश्वसनीय स्थिति देश में कभी नहीं हुई। चुनाव प्रणाली से लेकर लोकतंत्र सब पर इतने गहरे सवाल खड़े हो गए हैं मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। यह तक बताने को तैयार नहीं कि बिहार की इतनी बड़ी जीत का कारण क्या है।ऐसा कौन सा मुद्दा था जिस पर जनता ने एनडीए को 202 सीटें दे दीं। प्रधानमंत्री जीत के बाद तमाम बातें कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस में विभाजन भी करवा रहे हैं। मगर एक मुद्दा ऐसा नहीं बता रहे जिस पर लोगों ने उन्हें ऐसा अभूतपूर्व समर्थन दिया हो। 20 साल से वहां नीतीश की सरकार थी। जिसमें अधिकांश समय भाजपा पार्टनर रही। 11 साल से खुद मोदी की केन्द्र में सरकार है। तो क्या यह प्रो इन्कमबेन्सी वोट था। उनके काम से जनता इतनी खुश थी कि उसने महागठबंधन के रोजगार हर परिवार में सरकारी नौकरी की

घोषणा पर कान ही नहीं दिए? रोजगार सरकारी नौकरी उसके लिए कोई विषय ही नहीं थे? केवल मोदी के चेहरे को देखकर वोट दिए? गोदी मीडिया का प्रचार तो यही है कि लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। उन्हें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं।मान लो अगर ऐसा भी है तो फिर इतनी बड़ी जीत पर बिहार में जश्न क्यों नहीं? बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं नीतीश के कार्यकर्ताओं के जश्न की कोई खबर नहीं आई। जीते हुए खेमे में भी खामोशी है। तो न कोई मुद्दा न कोई जश्न! मतलब यह जीत जनता की कार्यकर्ताओं की मशीनरी से मिल कर मनचाहे नतीजे लेने लगे। न्याय व्यवस्था खामोश रहे। और मीडिया इस जीत को उन कारनामों को सही ठहराए। कांग्रेस की गलतियां होंगी। तेजस्वी में कमी होगी। मगर क्या अगर एसआईआर के नाम पर 69 लाख वोट नहीं काटे गए होते, हरियाणा से ट्रेन भर–भर कर लोग नहीं ले जाए गए होते, बहुत बड़ी तादाद में नए नाम नहीं जोड़े होते, ऐसे लोग नहीं होते जिन्होंने हरियाणा में दिल्ली में फिर बिहार में वोट नहीं डाले होते तो भी क्या ऐसे ही नतीजे आते? कांग्रेस ने ऐसे 8 सवाल पूछे हैं। मीडिया में आपको कहीं नहीं दिखेंगे। गोदी मीडिया मोदी की हर चीज को जस्टिफाई करने के अलावा वह हर चीज छुपाता भी है जो उनके खिलाफ जाती है। ऐसे में राहुल ही एकमात्र आशा की किरण नजर आते हैं। एक, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे डरते नहीं हैं। वैसे तो 2004 से जब से वे राजनीति में आए तब से उनके खिलाफ मगर सरकार में आने के बाद 2014 से बुरी तरह उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। ऐसी कोई कोशिश नहीं छोड़ी जिससे राहुल को नुकसान नहीं पहुंचा सकें। लोकसभा सदस्यता छिनने, मकान छिनने, ईडी की पूछताछ, दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे, सड़क पर धक्का मारकर गिराने जैसी हरकतें –क्या नहीं किया? इसके अलावा हजारों करोड़ रुपया उनका चरित्र हनन करने पर खर्च किया गया। एक लड़ने वाले आदमी को पप्पू के रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई। जो लोकसभा से लेकर विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में वहां के सिनेटरों (सांसदों, चुने हुए प्रतिनिधियों) के सामने बिना प्राम्प्टर के बोलता हो, हर सवाल को लेता हो उसे हल्का दिखाने की कोशिश की गई। प्रेस कान्फ्रेंस तो जाने कितनी करते हैं। हर सवाल लेते हैं। और अभी जब से वोट चोरी पर करना शुरू की है तो मंच पर अकेले होते हैं। बिना किसी सहायता के बोलते हैं। भयानक विडम्बना है यह कि सैकड़ों पत्रकार यह सब अपनी आंखों से देखते हैं। प्रेस कान्फ्रेंसों में मौजूद रहते हैं।

बिजली बकायदारों पर सख्ती, 50 हजार बिल होते ही काट दी जाएगी बिजली

लखनऊ, (संवाददाता)। आपके घर और दुकान पर यदि 50 हजार रुपये से ज्यादा का बिल बाकी तो आपकी बिजली कभी भी गुल हो सकती है। दरअसल, वर्टिकल सिस्टम में बिजली बिल के बकायेदारों और उपकेंद्र कर्मियों के बीच कटे कनेक्शन को गुपचुप जोड़कर बिजली चालू करने के खेल को खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए वर्टिकल सिस्टम की कलेक्शन इकाई ने 2.25 लाख बकायेदारों से बिल की वसूली कर उनकी देनदारी को शून्य करने का पहला लक्ष्य तय किया है। इन पर अनुमानित 75 करोड़ का राजस्व बकाया है। सबसे पहले उन बकायेदारों पर कार्रवाई होगी, जिन पर 50 हजार या इससे ज्यादा की देनदारी है। वह उपभोक्ता भी निशाने पर होंगे जिन्होंने पिछले छह माह से बिल का भुगतान नहीं किया है। राजधानी में सोमवार से 50 हजार रुपये के देनदारी वाली उपभोक्ताओं के घर एवं दुकान पर कलेक्शन टीम की दस्तक शुरू हो जाएगी। यह टीम बकायेदारों को बकाया रकम का बिल देकर निर्धारित अवधि में जमा करने का अल्टीमेटम देगी। तय अवधि में बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटा जाएगा। ऐसे कटे कनेक्शन को बिल चुकाए बिना जोड़ने पर उपकेंद्र के संविदा कर्मी की नौकरी जाएगी। साथ ही, काटे गए कनेक्शन की निगरानी होगी, जिससे गुपचुप उसे जुड़वाया न जा सके। अमौसी जोन में सर्वाधिक 1.50 लाख उपभोक्ता बिजली बिल के बकायेदार हैं। इनमें तो 1.10 लाख ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले छह माह से बिजली तो खूब जलाई, मगर बिल नही भरा है। यह बकायेदार निगोंहा, मोहनलालगंज, गोसाईंगंज, अमेठी, उतरेटिया, सरोजनीनगर, बंथरा, मोहान रोड,काकोरी, रहीमाबाद, मलिहाबाद, माल, जेहटा आदि के हैं। फतेहगंज निवासी बी लाल एक ऐसे बकायेदार उपभोक्ता हैं जिन पर तीन लाख रुपये की देनदारी है, मगर उनके घर की बिजली जल रही है। यह कृपा फतेहगंज उपकेंद्र के कुछ संविदा कर्मियों की है। संविदा कर्मियों ने इस कनेक्शन को सरकारी रिकॉर्ड में कटा दर्शा कर खुलेआम बिजली जलवा रहे हैं।

कुलपति ने किया सेमेस्टर परीक्षाओं का निरीक्षण तीन जिलों में हुई सुचितापूर्ण शुरुआत

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएँ मंगलवार को गाजीपुर के 155, जौनपुर के 138 और प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र पर प्रारंभ हुईं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने जौनपुर जनपद के गुलाबी देवी महाविद्यालय, सिद्दीकपुर का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने हेतु जारी सभी दिशा–निर्देशों का महाविद्यालयों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए। यदि किसी महाविद्यालय को परीक्षा संचालन में कोई समस्या आती है तो वह तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करे, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी का लाइव लिंक विश्वविद्यालय के केंद्रीय निरीक्षण कक्ष से जुड़ा होना अनिवार्य है। इसी क्रम में प्रथम पाली में जनपद जौनपुर के मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज एवं शिया पीजी कॉलेज के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह द्वारा किया गया। आज स्नातक स्तर के संगीत गायन, उर्दू, संस्कृत और बायोटेक्नोलॉजी तथा परास्नातक स्तर के रसायन विज्ञान (इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री), परास्नातक गणित, प्राणी विज्ञान,और भौतिकी (क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स) के प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ गाजीपुर के 155, जौनपुर के 138 तथा प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र पर सम्पन्न हुईं।

संक्षिप्त खबरें

कौशल व नवाचार को बढ़ावा देगा स्पार्क्स क्लब

लखनऊ, (संवाददाता)। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग की ओर से स्थापित 'स्पार्क्स क्लब' की शुरूआत शनिवार को कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने की। यह क्लब छात्रों में तकनीकी कौशल, नवाचार और प्रोजेक्ट–आधारित सीख को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वहीं, अंग्रेजी विभाग की ओर से भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित सेमिनार हुआ। इस मौके पर प्रो. सैयद हैदर अली, प्रो. अब्बास अली महदी (कुलपति, एरा विश्वविद्यालय), डॉ. रुचिता सुजय चौधरी और डॉ. हारुन रशीद मौजूद रहे।

गोंड समाज की उपजातियों को न्याय दिलाने का लिया संकल्प

लखनऊ, (संवाददाता)। मूलवासी कश्यप निषाद गोंड जन उत्थान समिति की ओर से रविवार को गोंड समाज की उपजातियों को न्याय दिलाने के लिए मल्हौर रोड चिनहट में संगोष्ठी हुई। मुख्य अथिति व मध्य प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव वीरेंद्र कुमार बाथम ने कहा कि अभिलेखों में मूल जाति गोंड दर्ज करानी होगी। अध्यक्ष डॉ. बिंद्रा प्रसाद धुरिया, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ गोंड व छविराज गोंड ने संगठित होकर गोंड समाज की उपजातियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। धुरिया सतीश कुमार कश्यप, राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य रमेश चंद गौड़ कश्यप, बिजनौर से हरीश चंद्र कश्यप, बाराबंकी से गया प्रसाद धुरिया, बस्ती से राजेंद्र धुरिया समेत 45 जनपदों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

मिस फेमिना ने मलिन बस्ती के बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ की नजाकत, नफासत बेहद पसंद है। घर पर जन्मदिन तो सभी मनाते हैं लेकिन मलिन बस्ती के बच्चों के साथ जन्मदिन मनाकर बेहद खुश हूं। बच्चों का जो प्यार मिला, उससे घर की याद नहीं आई। यह कहना है मिस फेमिना–2024 की विजेता मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल का। वे रविवार को इंदिरा नगर सेक्टर–19 स्थित आशा वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यालय पर सुबह 10:30 बजे पहुंचीं। केक काटने के बाद 30 बच्चों को स्टेशनरी व 20 महिलाओं को साड़ियां बांटी। वह मिस वर्ल्ड 2026 की तैयारी में जुटी हैं। फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनी वर्मा, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. एमपी. श्रीवास्तव, ज्योति मल्होत्रा, राहिला खान, विभा श्रीवास्तव, किरन सक्सेना सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

समूहगान प्रतियोगिता में एसजीएम इंटरनेशनल स्कूल प्रथम

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में रविवार को भारत विकास परिषद की ओर से क्षेत्र स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता हुई। प्रांत स्तर से चयनित विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। जिनमें कानपुर के ब्रह्मावर्त स्थित एसजीएम इंटरनेशनल स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चयनित टीम आगामी राष्ट्रीय स्तरीय समूहगान प्रतियोगिता में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र स्वरूप शुक्ल ने कहा कि भारत विकास परिषद सदैव संस्कार, सेवा और समर्पण के माध्यम से समाज से जुड़े रहने का कार्य करता रहा है। मुख्य अतिथि भानु प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पर्यवेक्षक प्रमोद कुमार त्रिपाठी, प्रांतीय महासचिव शशिकांत सक्सेना, प्रांतीय कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल सहित अन्य शामिल हुए।

तीन नोटिस के बाद भी सुधार न हुआ तो डॉक्टर होंगे बाहर

लखनऊ, (संवाददाता)। अब किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से बिना कारण बताए चिकित्सक गायब नहीं हो सकेंगे। ऐसा होने पर अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। सीएमओ का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों को हर हाल में इलाज मुहैया कराना प्राथमिकता में है। लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ के अधीन 20 सीएचसी, 54 पीएचसी और 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) संचालित हो रहे हैं। कई केंद्रों पर चिकित्सक के अनुपस्थित रहने की शिकायतें आती है। सीएमओ ने सभी प्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। बिना बताए गायब होने पर अधीक्षक से ही स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा है कि समाज के हर तबके के व्यक्ति को समय से स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। इसको लेकर विभाग गंभीर है। बाद कार्य में सुधार न होने पर सेवाएं समाप्त कराने की संस्तुति होगी।

प्रदेश में घट जाएंगी पांच से आठ फीसदी बिजली दरें

लखनऊ, (संवाददाता)। निजीकरण के विरोध में देशभर के बिजली कर्मी और अभियंता लामबंद हैं। 30 जनवरी को दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की रविवार को फील्ड हास्टल में हुई बैठक में तय किया गया कि हर जिले से बिजलीकर्मी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। निजीकरण के विरोध में 15 नवंबर से अलग–अलग स्थानों पर सम्मेलन शुरू हो गए हैं, जो 15 जनवरी तक चलेंगे। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ निजीकरण किया जा रहा है तो दूसरी तरफ वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है। निजीकरण के लिए लाए गए ड्राफ्ट बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इसे केंद्र सरकार तत्काल वापस नहीं लेती है तो 30 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित रैली में हर जिले से बिजलीकर्मी हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि बिजली कर्मियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) ने किसान और सामान्य उपभोक्ता संगठनों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर बिजली के निजीकरण और बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। संयुक्त मोर्चे की पहली बैठ 14 दिसंबर को दिल्ली में होगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश सरकार और विद्युत नियामक आयोग से मांग की है कि बिजली दरों में पांच साल तक करीब आठ फीसदी की कमी की जाए। क्योंकि वितरण निगमों पर उपभोक्ताओं का करीब 33122 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। बिजली दर में कमी करके निगम उपभोक्ताओं का बकाया लौटाए। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली दरों के नए ऐलान में लगातार देरी की जा रही है। उपभोक्ताओं का बिजली निगमों में 33122 करोड़ सरप्लस पहले से चल रहा है, जबकि करीब 4000 करोड़ इस बार भी बढ़ जाएगा। ऐसे में नियमानुसार प्रदेश में किसी भी कीमत पर बिजली दर नहीं बढ़ाई जा सकती है। उपभोक्ताओं का निगमों पर लंबे समय से सरप्लस चल रही रकम की अदायती के लिए पांच साल तक कम से कम आठ फीसदी की तरह से बिजली कम की जाए।

संक्षिप्त खबरें

आशा के जरिये दंपती को बच्चा दिलाने के मामले की जांच ठंडे बस्ते में

लखनऊ, (संवाददाता)। नगराम में आशा कार्यकर्ता के जरिये दंपती को बच्चा दिलाने के मामले की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नोटिस जारी कर मामले को भूल गए। अभी तक न आशा और न अस्पताल संचालक के बयान दर्ज हुए हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि वह बच्चा आखिर किसका था और कहां से लाया गया था। मोहनलालगंज के समेसी निवासी किसान रामहर्ष विक्रम (61) और उनकी पत्नी मायावती के मुताबिक, 12 अगस्त को उनके घर आई आशा कार्यकर्ता ने उन्हें नबीनगर चौराहा स्थित क्लीनिक में मानसिक मंदित महिला के बच्चे को जन्म देने की जानकारी दी। दंपती आशा के साथ वहां गए और बच्चे को साथ ले आए। हालांकि, अस्पताल से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था, जिसके बाद दंपती ने बच्चे को कानूनी हक दिलाने के लिए डीएम और सीएमओ को पत्र भेजने के साथ ही समाधान दिवस में भी गुहार लगाई। मामले का खुलासा होने के बाद, बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया ।

जन आरोग्य मंदिरों का हाल, कहीं इलाज बंद, कहीं जांच ठप

लखनऊ, (संवाददाता)। हर रविवार को लगने वाले आरोग्य मेले में मरीजों को इलाज और जांच की पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई केंद्रों पर न डॉक्टर हैं, न लैब टेक्नीशियन। नतीजतन मरीज बिना इलाज और बिना जांच लौट रहे हैं। पड़ताल में यह हकीकत सामने आई है। यहां डॉक्टर मौजूद थे और मरीजों को बीमारी के आधार पर परचे जारी कर रहे थे। डेंगू, मलेरिया और सीबीसी जांच की सुविधा केंद्र पर उपलब्ध है, लेकिन सभी जांच बंद मिलीं। प्रभारी ने बताया कि लैब टेक्नीशियन अवकाश पर है, इसलिए जांच नहीं हो पा रही है। मरीजों को सिविल अस्पताल या अन्य केंद्रों पर भेजा जा रहा है। न्यू हैदराबाद केंद्र पर निरीक्षण के समय डॉक्टर नहीं मिले। स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर चिकित्सकीय अवकाश पर हैं और उनकी जगह किसी अन्य डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। बीमारी बताने पर स्टाफ ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा देने से मना कर दिया। डॉक्टर 18 तारीख तक अवकाश पर हैं, इसलिए मरीजों से कहा गया कि वे दूसरे केंद्र जाकर इलाज कराएं। ऐसे में कई मरीज निराश होकर लौट गए।

लखनऊ में छात्राओं ने दी अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा

लखनऊ, (संवाददाता)। संचालित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा–2025 के दूसरे चरण की परीक्षा रविवार को 33 शहरों के 34 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। 9वीं से 12वीं कक्षा के 20 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के लिए बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस बार परीक्षार्थियों की उपस्थिति में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से बच्चे पहुंचने शुरू हो गए थे। परीक्षा दो पालियों में संपन्न हुई। विद्यार्थियों ने लिखित परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से दी। लखनऊ में मोहान रोड स्थित राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज परिसर में 27 छात्राओं ने सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा दी। इस दौरान उनके सहयोग में अन्य 27 छात्र–छात्राएं भी शामिल हुए।।

समाजवादी पार्टी मुख्यालय में वीरांगना ऊदा देवी का बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में आज वीरांगना ऊदा देवी का बलिदान दिवस सादगी और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी द्वारा ऊदा देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद सांसद आर.के. चौधरी और सांसद नरेश उत्तम पटेल ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर वीरांगना के अदम्य साहस को नमन किया।अखिलेश यादव का मानना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के सिकंदरबाग में हुए भीषण युद्ध के दौरान ऊदा देवी ने अकेले 36 अंग्रेज सैनिकों का सामना कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। उनकी शहादत का सम्मान करते हुए सार्जेंट क्विकर वालेसकृजिसकी गोली से ऊदा देवी शहीद हुई थींकृने भी उनका अदब करते हुए अपनी टोपी उतारकर सलामी दी थी। कई विदेशी लेखकों और इतिहासकारों ने भी इस वीरता का विस्तृत वर्णन किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऊदा देवी का यह बलिदान भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का अविस्मरणीय अध्याय है।कार्यक्रम में सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि भारतीय समाज और इतिहास ने वीरांगना ऊदा देवी पासी को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे योग्य थीं। उन्होंने कहा कि समाज के वास्तविक कल्याण का मार्ग पीडीए के सिद्धांतों से होकर गुजरता है। वहीं सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज समाजवादी पार्टी के कंधों पर है।कार्यक्रम में अरविन्द कुमार सिंह (पूर्व सांसद), गौरव रावत (पूर्व विधायक), राजेन्द्र यादव, अम्ब्रीष पुस्कर, जिलाध्यक्ष जयसिंह जयंत, पूर्व प्रत्याशी सोनू कनौजिया, राजबाला रावत, ब्लॉक प्रमुख ऊषा सेन, विजय सिंह, शब्बरी अहमद खान, आदर्श सिंह एडवोकेट, मनोज पासवान, उमाशंकर वर्मा, तरुण रावत, राम प्रकाश यादव, शशिलेन्द्र यादव, राम समुझ रावत, सतेन्द्र, यशवीर लोधी, शिव शंकर राजपूत, सुहागवती, विजयलक्ष्मी निषाद, सविता सरोज, उर्मिला रावत, आशा यादव, बचान सिंह, चन्द्रशेखर, जीतू कश्यप, रीतू पासी, विजय लाल, सुनील रावत, अर्चना रावत, रत्नेश रत्ना, पृथ्वीपाल रावत सहित अनेक कार्यकर्ता और समाजिक प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।कार्यक्रम का समापन वीरांगना ऊदा देवी के शौर्य, साहस और बलिदान को याद करते हुए उन्हें राष्ट्र की नारीदृशक्ति और संघर्षदृ परंपरा का प्रेरणास्रोत बताते हुए हुआ।

ग्राम बहरौरा में मिशन शक्ति5.0 के तहत महिला सुरक्षा पर व्यापक चौपाल

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना माल कमिश्नरेट द्वारा ग्राम पंचायत बहरौरा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए एक प्रभावी ग्राम चौपाल एवं पुलिसदृजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा संसाधनों और आवश्यक हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान को मजबूती दी जा रही है। इसी क्रम में जिले के 54 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा महिला उप निरीक्षक की तैनाती की गई है ताकि थानों पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण हो सके।थाना माल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप निरीक्षक अमरपाल, महिला उप निरीक्षक सपना देवी, कांस्टेबल मोहम्मद जाहिद और महिला पीआरडी माधुरी ने स्थानीय जनता, विशेषकर महिलाओं के साथ संवाद किया। टीम ने मिशन शक्ति से संबंधित योजनाओं, महिला सुरक्षा उपायों तथा कानूनी सहायता के उपलब्ध माध्यमों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।कार्यक्रम में महिलाओं को रोजमर्रा की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों 1090, 1098, 1076, 1930, 101, 112 और 108 के बारे में बताया गया। साथ ही साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक करते हुए उनसे बचने के उपाय समझाए गए। पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया।

पूरे प्रदेश में आयोजित हुआ 227वां मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में आमजन, विशेषकर समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला अपने 227वें चरण में शुक्रवार, 16 नवंबर 2025 को पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया। 2 फरवरी 2020 से निरंतर आयोजित हो रहे इन मेलों ने स्वास्थ्य जांच, उपचार, गोल्डेन कार्ड वितरण और जन–जागरूकता अभियानों के कारण आम जनता में व्यापक विश्वास और लोकप्रियता हासिल की है।स्वास्थ्य मेलों में आने वाले सभी नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा जांच, परामर्श और उपचार उपलब्ध कराए गए। साथ ही लोगों को व्यक्तिगत व पर्यावरणीय स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। जलजनित रोगों से बचाव, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से सुरक्षा हेतु जागरूकता बढ़ाई गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को मच्छरदानी के उपयोग, पानी जमा न होने देने और स्वच्छता अपनाने की सलाह दी गई।मेले में शुद्ध पेयजल, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और तंबाकू के दुष्प्रभावों पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। गैर–संचारी रोगों से बचाव, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए विशेषज्ञों ने लोगों से सीधे संवाद किया। गंभीर रोगियों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की मदद से उच्च स्तरीय चिकित्सा केंद्रों पर तत्काल रेफर किया गया। वहीं बड़ी संख्या में गोल्डेन कार्ड बनाकर लोगों को सौंपे गए।आज आयोजित 227वें आरोग्य स्वास्थ्य मेले में कुल 1,90,142 रोगियों ने लाभ प्राप्त किया,।

हाथरस में ऐतिहासिक कंस वध एवं श्रीकृष्ण बलराम प्रस्थान लीला में शामिल हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, 135 वर्ष पुरानी परंपरा की प्रशंसा ऊर्जा सुधारों पर दिए महत्वपूर्ण संदेश

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज हाथरस के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित कंस वध एवं श्रीकृष्णदृबलराम प्रस्थान लीला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभाग किया। ब्रज संस्कृति की पहचान बन चुकी यह लीला 135 वर्षों से लगातार आयोजित की जाती रही है, जिसे देखने के लिए दूर–दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने पर मंत्री का आयोजकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गरमजोशी से स्वागत किया। परंपरागत विधि–विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और पूरा मैदान सांस्कृतिक भक्ति–मय वातावरण से भर उठा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने हाथरस की इस अनूठी सांस्कृतिक परंपरा की हृदय से सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ब्रज संस्कृति की आत्मा का जीवंत और भव्य स्वरूप है। उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुसार आज ही के दिन द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण और बलराम अत्याचारी कंस का वध करने के लिए अपनी सेना और साथियों के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे। उसी दिव्य ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में हाथरस में यह लीला हर वर्ष आयोजित की जाती है, जो 135 वर्षों से बिना रुके चल रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस ब्रज क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है और यहाँ की मिट्टी में राधा–कृष्ण की लीलाओं की सुगंध और स्पंदन आज भी महसूस किया जा सकता है।अपने संबोधन में मंत्री ने ऊर्जा और नगर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक विद्युत सेवाएँ उपलब्ध कराना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे स्मार्ट मीटर अपनाकर इस दिशा में सरकार के प्रयासों को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर भविष्य की आधुनिक तकनीक का हिस्सा हैं, जो बिजली वितरण को सटीक, पारदर्शी और उपभोक्ता हितों के अनुरूप बनाते हैं।मंत्री ने उपस्थित नागरिकों से आग्रह किया कि वे स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट मीटर प्रणाली को स्वीकार करें और ऊर्जा सुधार प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट मीटरों से संबंधित किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि बिजली से जुड़ी लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि जनता को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार निरंतर ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोच्च महत्व देती है।कार्यक्रम के अंत में उन्होंने हाथरस के लोगों को इस ऐतिहासिक परंपरा को शानदार ढंग से निभाए रखने के लिए बधाई दी और विश्वास जताया कि ब्रज संस्कृति का यह गौरवपूर्ण आयोजन आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिला निर्वाचन अधिकारीधजिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र द्वारा तहसील मड़ियाहूं के सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य के तहत फॉर्मो के डिजिटाइजेशन कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए अद्यतन प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान उन्हों ने पाया कि फॉर्मों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि गति बढ़ाते हुए आज 20,000 फॉर्मों का डिजिटाइजेशन कार्य सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्मिकों को जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि फॉर्म भरने, संग्रहण तथा तकनीकी प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए सभी कार्मिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन गंभीरता से करें और अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी ने ठस्द्वारा घर–घर जाकर मतदाता सूची से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की स्थिति, कार्य की प्रगति एवं गणना प्रपत्रों की जानकारी का सत्यापन, फॉर्म वितरण, संकलन एवं उसकी वापसी की वास्तविक स्थिति, डिजिटाइजेशन प्रक्रिया की गति एवं गुणवत्तापूर्ण फीडिंग कार्य, मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रगति के संबंध में जानकारी ली और और निर्देश दिए कि मा० भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य को समयबद्ध रूप से संपादित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ईआरओ, एईआरओ सुपरवाइजर एवं बीएलओ आपसी समन्वय बनाते हुए यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो तथा संशोधन एवं शुद्धिकरण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब मतदाता अवजमत.मबप.हवअ.पद पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं मतदाता पहचान पत्र संख्या के माध्यम से गणना प्रपत्र (फॉर्म) को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। यह सुविधा मतदाताओं को प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सरलता प्रदान करती है। इसके पूर्व 17 नवम्बर 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारीध जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चंद्र द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मल्हनी में किए जा रहे कार्यों की प्रगति का आकस्मिक निरीक्षण और विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने बीएलओ (ठस्) से दूरभाष के माध्यम से गणना प्रपत्र के वितरण और संग्रहण के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी रामअक्षयबर चौहान, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, ईआरओ, सुपरवाइजर सहित अन्य उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति फेज–5 के तहत पीयू में छात्राओं को मिल रहा तकनीकी सशक्तिकरण का प्रशिक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के निर्देशानुसार तथा मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज–5 के अंतर्गत कंप्यूटर एप्लिकेशन शॉर्ट टर्म कोर्सेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉ. जाह्नवी

श्रीवास्तव ने बताया कि छात्राओं को तकनीकी ज्ञान से सशक्त करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य छात्राओं को रोजगारपरक ज्ञान देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रम की संयोजक एवं ट्रेनर डॉ. सोनम झा ने बताया कि 30 छात्राओं का एक बैच तैयार किया गया है, जिसमें थ्योरी के साथ–साथ प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ नई तकनीकों का भी समावेश किया गया है। सह–समन्वयक प्रियंका जायसवाल ने बताया कि सभी छात्राएं अत्यंत उत्साह और रुचि के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और इस पाठ्यक्रम से उन्हें उपयोगी तकनीकी ज्ञान मिल रहा है, जो उनके भावी करियर में सहायक सिद्ध होगा।

संक्षिप्त खबरें

भ्रष्टाचार के पर्याय बने ए आर सहकारिता एवं रसद, खाद के दो कर्मचारी

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं पर पदधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता शिव सेवक गुप्त एवं वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह के संयुक्त नेतृत्व में मंगलवार को हरदोई जनपद में भ्रष्टाचार के पर्याय बने ए आर सहकारिता एवं रसद, खाद के दो कर्मचारी क्रमशः मनोज शर्मा एवं धर्मेंद्र के विरुद्ध जिला अधिकारी को शिकायती पत्र कार्रवाई हेतु मांग पत्र सोपा गया इस अवसर पर संयुक्त अधिवक्ता परिषद के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह ने बताया जनपद के किसानो का शोषण लगातार

जारी है उन्होंने बताया सरकार का रवैया पारदर्शी, किसान हित में है परंतु उक्त स्थानीय कर्मचारियों के लापरवाही और भ्रष्टाचारी नियति वास्तव में किसान हित में घातक है यदि शीघ्र ही उक्त भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं लिखी गई तो संयुक्त अधिवक्ता परिषद सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन चलाएगा इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी । इस अवसर पर प्रमुख रूप से संयुक्त अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता शिव सेवकगुप्त एवं जिला संगठन मंत्री अधिवक्ता शुभम गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता,जिला मंत्री अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता जिला मंत्री अधिवक्ता अमर सिंह, जिला प्रचार मंत्री अधिवक्ता अंकित गुप्ता , संयुक्त मानवाधिकार परिषद के प्रदेश प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह बबलू सहित दर्जन पदाधिकारी ने जिला अधिकारी को मांग पत्र प्रेषित कर आक्रोश के साथ कार्रवाई की मांग की है

जनशिकायतों का निस्तारण समय से करें निगम कर्मी - महापौर

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जनशिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम कार्यालय में आयोजित संभव कार्यक्रम में मंगलवार को कुल 18 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए।जिसमें से 11 का महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने तुरंत समाधान कराया, जबकि सात प्रकरण गली एवं नाली निर्माण से जुड़े थे।जिसकी जांच कर स्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे महापौर ने कहा कि जनशिकायतों का समाधान गुणवत्तापूर्ण और प्राथमिकता पर हो।इस मामले में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर। उन्होंने सफाई एवं एंटी लार्वा छिड़काव के लिए तत्काल कर्मचारियों को रवाना किया।उन्होंने जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र तुरंत जारी करने का निर्देश दिया।इस दौरान अश्विनीपुरम कॉलोनी के अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने आरसीसी सड़क निर्माण की मांग की, जबकि आदित्य उपाध्याय ने वजीरगंज चेला छावनी में नाले की मरम्मत तथा पप्पू सोनकर ने पेयजल समस्या से महापौर को अवगत कराया। व्यापार मंडल की ओर से आए प्रार्थनापत्र में बजाजा में अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा जताई गई।रजनीश तिवारी ने कैलाशपुरी में कूड़ा करकट हटवाने एवं जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। आशापुर झलकारीबाई वार्ड के पवन कुमार, रामकुमार आदि ने नाली व सड़क निर्माण की आवश्यकता जताई।इसी तरह अन्य लोगों ने भी अपनी समस्या से अवगत कराया।नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडेय ने बताया कि नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने समस्याओं का निदान कराया।जनसुनवाई में पूर्व उपसभापति जय नारायण सिंह रिंकू, पार्षद अनुज दास, रमाशंकर निषाद एवं अनूप श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त डॉ नागेंद्र नाथ, जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता निर्माण भारत सिंह मौजूद रहे।

सीओ सिटी ने महिला थाना परिसर मे छात्राओं व महिलाओ को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

अयोध्या।सोमवार को महिला थाना परिसर मे सीओ सिटी शैलेन्द्र सिंह ने महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के साथ ष्मिशन शक्ति फेज 5.0' अभियान के तहत परिसर मे आई छात्राओं व पीडित महिला फरियादियो को सुरक्षा संबंधित जानकारी दिया।इस मौके पर उन्होंने छात्राओं,फरियादी महिलाओ को पंपलेट, पोस्टर के माध्यम से जागरूक करते हुए कहा कि मुसीबत के समय आप घबराये नहीं बल्कि छेडछाड करने वाले अराजक तत्वों सें निपटे और समय रहते इसकी सूचना महिला सहायता केंद्र व स्थानीय पुलिस थानो व पुलिस चौकी पर दे।इसके अलावा उन्होंने शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में बालिकाओं /महिलाओं को जागरूक किया गया और महिला अपराध संबंधित अपराध के बारे मे बताया।वही विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के महत्व के बारे बताया।इस मौके पर उप निरीक्षक सोनी, श्वेता राठौर, प्रिया, चेतना सहित महिला आरक्षी लक्ष्मी प्रजापति, जय श्री सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रही।

गीतांजलि जौनपुर द्वारा 30 जरूरतमंदों लोगों को दिया गया कंबल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर धार्मिक सामाजिक एवं रचनात्मक संस्था गीतांजलि जौनपुर द्वारा कंबल वितरण की श्रृंखला में इस बार कंबल वितरण का कार्यक्रम संस्था के विशिष्ट सदस्य श्री राम प्रकाश पांडे मुन्ना प्रधान , एवं गीतांजलि संरक्षक श्री अमरीश पांडे जी) के कर कमलों द्वारा उनके मठ

चंबल तारा हरदीपुर पर 30 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया जिसमें संस्था के संरक्षक चंद्र प्रताप सोनी जी ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया जिसमें संस्था के अध्यक्ष नीरज शाह उपाध्यक्ष अमन सहगल महासचिव रामानंद विश्वकर्मा कोषाध्यक्ष पवन सोनी सहकोषाध्यक्ष अशोक मौर्य विसर्जन प्रभारी ऋषभ माली सांस्कृतिक सचिव अमित सैनी देवेश साहू वरिष्ठ सदस्य संजीव कुमार सिंह एवं मठ के गण मान्य नागरिकों में महिमा पांडे अरविंद पांडे योगेंद्र नाथ पांडे राहुल पांडे आदि की उपस्थिति सराहनी रही और कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्थानीय लोगों का विशेष सहयोग रहा और कार्यक्रम के अंत में प्रधान श्री राम प्रकाश पांडे जी द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और इस ठंड को देखते हुए संस्था के सभी पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए संस्था द्वारा आगे भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे।

संक्षिप्त खबरें

25 नवंबर को राममंदिर पर पीएम मोदी के बटन दबाते ही 10 सेकेंड में फहरा उठेगा ध्वजा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। 25 नवंबर को राममंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।25 नवंबर को पीएम मोदी बटन दबाकर ध्वजा को फहराएंगे।उनके साथ आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे।जानकारो की माने तो इसके लिए 12 बजे से 12.30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है।बटन दबाने के बाद 10 सेकेंड में ही ध्वज हवा में फहराने लगेगा। केसरिया रंग की खास ध्वजा पर सूर्य, ध और कोविदार (अयोध्या का शाही वृक्ष, जो कचनार के नाम से जाना जाता है) के प्रतीक बने हुए हैं।ये सभी चिह्न सूर्यवंश के प्रतीक है।ध्वज को वैदिक मंत्रों के बीच सलामी दी जाएगी।ध्वज फहराते ही मंदिर परिसर में घंटे–घड़ियाल बजने लगेंगे।राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है।इसी स्तंभ पर 22 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी पताका फहराएगी।जो कि 3 किमी दूर से दिखेगी।ध्वजा फहराने के लिए ऑटोमैटिक फ्लेग होस्टिंग सिस्टम लगाया गया है।ध्वज बदलने के लिए भी इस सिस्टम की मदद ली जाएगी।हालांकि, ट्रस्ट ने

अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने–कितने अंतराल के बाद ये ध्वजा बदली जाएगी।हवा के बहाव के साथ ध्वजा 360 डिग्री पर घूम सकेगी।राम मंदिर में पहली बार राम–सीता विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 8 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है।इनमें से ढाई हजार लोगों के रुकने के लिए तीर्थ पुरम में टेंट सिटी बसाई जा रही है। 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोग दर्शन नहीं कर सकेंगे।ट्रस्ट के अनुसार, भक्त 26 नवंबर को ही दर्शन कर सकेंगे।अयोध्या में पीएम मोदी का दौरा 3 घंटे का होगा।वे 11 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे।पीएम मोदी राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे।वहां दर्शन–पूजन करेंगे।वह रामलला समेत राम दरबार के दर्शन कर आरती उतारेंगे।अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12.30 के बीच 191 फीट ऊंचे शिखर पर पीएम मोदी ध्वजा रोहण करेंगे।पीएम सप्त मंदिर परकोटा, शेषावतार मंदिर और रामायण के श्री डी म्यूरल्स भी देख सकते हैं।फिर वो मंदिर में काम करने वाले इंजीनियर और श्रमिकों से मुलाकात कर सकते हैं।उनके लिए मां अन्न पूर्णा मंदिर के पीछे ग्रीन हाउस तैयार किया गया है।एसपीजी ने यहां की सिक्योरिटी अपने कब्जे में रखी है।अहमदाबाद के कारीगरों द्वारा तैयार राम मंदिर पर फहराने वाली ध्वजा कई मायनों में खास है।ध्वजा को विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो धूप, बारिश और तेज हवा से सुरक्षित रहेगा।इसमें नमी और तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए डबल कोटेड सिंथेटिक परत बनाई गई है।ध्वज पर सूर्य वंश, ध, कोविदार वृक्ष के चिह्न बनाए गए हैं।राम मंदिर पर फहराने वाली ध्वजा को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ये तिरुपति बालाजी की तर्ज पर हर रोज बदली जाएगी।ट्रस्ट के मुताबिक, ऑटोमैटिक सिस्टम की वजह से इस ध्वजा को बदलने के लिए पुजारियों को शिखर पर ऊपर नहीं जाना होगा।जिस तरह से बटन दबाकर ध्वजा फहराई जाएगी।उसी तरह से कंट्रोल रूम से ध्वजा को नीचे भी लाया जा सकेगा।पुजारी इस ध्वजा को आसानी से बदल लेंगे।हालांकि, अभी तक तय नहीं किया गया कि ध्वजा कितने अंतराल पर बदली जाएगी।

जौनपुर में भी जगेगी देहदान की अलख

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व कानपुर से प्रारम्भ हुआ देहदान का अभियान अब प्रदेश के अधिकांश जिलों में अपना विस्तार करने के बाद अब जौनपुर में देहदान की अलख जगाने की तैयारी में है। इसी क्रम में देहदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन मंगलवार को स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो0 आर बी कमल द्वारा किया गया।मुख्य अतिथि कानपुर से विशेष रूप से आये देहदान अभियान प्रमुख मनोज सेंगर एवं माधवी सेंगर ने बताया कि 15 नवम्बर 2003 को तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश आचार्य विष्णुकान्त शास्त्री जी के आग्रह पर कानपुर के जे० के० कालोनी जाजमऊ स्थित एक कमरे में परिवार के सात सदस्यों द्वारा देहदान संकल्प से प्रारम्भ हुआ अभियान अब ष 'युग दधीचि देहदान अभियान' ष्के रूप में पूरे प्रदेश के दर्जनों राजकीय मेडिकल कालेजों को अब तक 308 मृत देह दान कर चुका है। इसमें एम्स रायबरेली और एम्स गोरखपुर भी शामिल हैं, अभी तक 4000 से अधिक लोगों ने देहदान संकल्प पत्र भर कर दिए हैं, किसी संकल्पकर्ता का निधन होने पर उसके मृत शरीर को पूरे सम्मान के साथ मेडिकल कॉलेज लाया जाता है यहां पर प्रार्थना, पुष्पांजलि एवं मंत्रपाठ करते हुए देह को एनाटॉमी विभाग को सौंप दिया जाता है, इसके बाद उस व्यक्ति के समस्त धार्मिक संस्कार वैदिक रीति से संस्था कानपुर में सम्पन्न कराती है पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज सेंगर ने बताया अभियान का प्रथम देहदान कानपुर देहात के डेरापुर से 21 वर्षीय बउआ दीक्षित का 20 अगस्त 2006 को हुआ था।अभियान की महासचिव माधवी सेंगर ने बताया कि देहदान में एक संकल्प पत्र भरा जाता है, एक हलफनामा और आधार की कापी लगती है, परिवार की सहमति आवश्यक है। एक फोटो भी लगेगा, 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है।अभियान प्रमुख मनोज सेंगर ने बताया कि एच आई वी, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, कोविड, सेप्टिसिमिया, शरीर में घाव, अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में देह स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके लिये मनोज सेंगर के फोन नंबर 9839161790 पर सम्पर्क कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि सेंगर दम्पति ने अपना दवा व्यवसाय त्याग कर आजीवन निः सन्तान रहने का प्रण करके पूरा जीवन ही देहदान अभियान के नाम कर दिया है, भारतीय समाज में किसी की मृत्यु होने पर उसका चितारोहण और अग्निदाह न हो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, समाज की इस आस्था से सीधे टकराने वाले और प्रचलित मान्यता को विपरीत दिशा में मोड़ कर समाज की सोच को सकारात्मक परिणाम की ओर प्रेरित करना बड़ा ही कठिन काम था लेकिन सेंगर

दंपति के 22 सालों के अथक प्रयासों ने वह संभव कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, अब हमें पूरा विश्वास है कि उनकी सहायता से हमें भी छात्रों के अध्ययन हेतु मृत शरीर उपलब्ध हो सकेंगे। क्यों आवश्यक है देहदान एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डाव भारती यादव ने बताया कि मानव देह की आन्तरिक संरचना समझने के लिये प्रथम वर्ष के चिकित्सा छात्रों को अध्ययन हेतु मृत देह की आवश्यकता होती है, आदर्श स्थिति में दस छात्रों पर एक देह होनी चाहिये पर कमी के चलते एक देह पर पच्चीसो छात्रों को सीखना पड़ता है इसी कमी को पूरा करने के लिए देहदान करना इस युग का सबसे बड़ा धर्म है, ।कॉलेज की पूर्व प्राचार्या एवं एनाटॉमी की डॉ रुचिरा सेठी ने कहा कि कालेज के एनाटमी विभाग में भी फार्म उपलब्ध है देहदान के इच्छुक यहां भी संपर्क कर सकते हैं, अब यहाँ के महार्षि दधीचि के वंशजों का आवाहन है कि वे आगे आकर अपनी देह का समर्पण मरणोपरान्त राष्ट्र हित में करें। कार्यक्रम में अभियान प्रमुख मनोज सेंगर, महासचिव माधवी सेंगर, डीन अकादमिक प्रोफेसर तबस्सुम यासमीन, उप प्रधानाचार्य प्रोफेसर आशीष यादव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ए ए जाफरी, प्रोफेसर उमेश सरोज, डा0 साधना अजय, डॉ विनोद कुमार, डा0 अरविंद पटेल, डा0 सरिता पाण्डेय, डा0 राजश्री यादव, डा0 अचल सिंह, डा0 हमजा अंसारी, डॉ0 नवीन कुमार, डा0 संजीव यादव, डा0 ममता, डा0 स्वाति विश्वकर्मा,डॉ प्रीति विश्वकर्मा, डा0 आशुतोष सिंह, डा0 अलीशा अंजुम, डा0 रेनू , डा0 पंकज, डॉ जयंत शर्मा, डॉ संदीप के साथ एनाटमी विभाग से डा अर्चना चौधरी एवं डॉ प्रियंका सिंह तथा एमबीबीएस छात्रष छात्राएं उपस्थित रहे।

यातायात माह दिवस के बावजूद जाम से नही निजात पा रहे शहरवासी

अयोध्या। यातायात माह दिवस व वीवीआईपी कार्यक्रम के बावजूद भी शहर के विभिन्न चौराहों तथा मार्गों पर जाम लगा रहा है, जो घंटो बना रहता है।इस समय शहर मे यातायात व्यवस्था राम भरोसे यातायात चल रही है।जबकि इस समय यातायात माह दिवस व राम मंदिर पर ध्वज रोहण कार्यक्रम को लेकर वीवीआईपी लोगो का आवाजाही भी लगा है।परंतु इसके बावजूद शहर का कोई ऐसा ही चौराहा या फिर मार्ग शायद ही बचा हो जहां पर आपको जाम ना मिले।और यह जाम केवल कुछ मिनट तक ही नहीं बल्कि कई घंटों तक आप इस जाम में फंसे रहेंगे यहां तक की इधर से गुजरने वाले खासकर एंबुलेंस के माध्यम से मरीज छात्रों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है।इस संबंध में जब यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका यही रटा रटाया उत्तर रहता है कि जाम की कोई समस्या शहर मे नहीं है।कोतवाली नगर क्षेत्र के कसाबबाडा, रिकाबगंज, जिला महिला चिकित्सालय, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, देवकाली बाईपास, नाका बाईपास, रायबरेली बाईपास मार्ग, चौक, फतेहगंज, रिकाबगंज, नियांवा,गुदरी बाजार सहित कई ऐसे प्रमुख चौराहे व मार्ग हैं जहां पर जाम लगना आम बात है।और यह जाम सुबह देर शाम तक बनी रहती है।जिसके चलते स्कूली बच्चे, मरीज, बाहर से आने वाले श्रद्धालु व अन्य राहगीर, दो पहिया व चार पहिया वाहन चालक इस जाम मे घंटो फंसे रहते

है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी ध्यान नहीं दे रहे है।देखा जाये तो इन चौराहों पर आपको एकाद यातायात के सिपाही मिलेंगे।आधा चौराहा आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ना तो यातायात सिपाही तैनात मिलेंगे और ना ही यातायात ट्रैफिक लाइट से भीड़ को कंट्रोल करते हुए मिलेगी।इस संबंध में जब यातायात एसपी एपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया की विभाग में यातायात पुलिस कर्मी पर्याप्त संख्या में है लेकिन प्रमुख चौराहों पर यातायात का नियंत्रण ट्रैफिक लाइट द्वारा होता है।

नवंबर यातायात माह पर पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान 'जान है, जहान है' थीम के साथ बच्चों को दिए सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण मंत्र

हरदोई। शासन के निर्देशपर पुलिस विभाग द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में जिलेभर के गली–नुक्कड़ों, स्कूल–कॉलेजों, बस स्टैंडों और प्रमुख चौराहों पर जागरूकता अभियान लगातार जारी है। अभियान का उद्देश्य आम जनमानस को ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इसी श्रृंखला में मंगलवार को कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव तथा प्रभारी निरीक्षक यातायात प्रमोद कुमार यादव ने स्थानीय विद्यालय में पहुंचकर 'जान है, जहान है' थीम पर बच्चों को सड़क सुरक्षा से जुड़े आवश्यक नियमों और जीवन को सुरक्षित रखने के उपायों की जानकारी दी। अधिकारियों ने हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग, सड़क पार करने के सही तरीके, ओवरस्पीडिंग के खतरे तथा मोबाइल का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान उप निरीक्षक डॉली शर्मा ने छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन न सिर्फ स्वयं की सुरक्षा के लिए बल्कि परिवार व समाज की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे स्वयं को जिम्मेदार नागरिक साबित करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।